Toppersnotes®
Unleash the topper in you

MPPSC

राज्य सिविल सेवाएँ

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

भाग - 4

आधुनिक इतिहास

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	1857 का विद्रोह	1
2	शिक्षा एवं प्रेस का विकास	7
3	सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलन	14
4	राष्ट्रवाद का जन्म (मध्यम चरण 1885–1905)	26
5	उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग चरमपंथी चरण	31
6	जन आंदोलन गांधीवादी युग (1917–1925)	44
7	स्वराज के लिए संघर्ष (1925–1939)	53
8	स्वतंत्रता की ओर (1940–1947)	71
9	स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण	81
10	महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाएँ	89
11	ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन	100

1 CHAPTER

1857 का विद्रोह

1857 के विद्रोह के कारण

1. राजनीतिक कारण:

- ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष विलय/साम्राज्यवादी नीति और व्यपगत सिद्धांत के तहत राज्यों को अधिगृहित कर लेना। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई।
- 1849 में, लॉर्ड डलहौज़ी ने घोषणा की कि बहादुर शाह II के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा।
- लॉर्ड डलहौज़ी ने अवध को कुप्रशासन के बहाने अपने कब्जे में ले लिया, जिससे हजारों रईस, अधिकारी, सेवक और सैनिक बेरोजगार हो गए।

> Note: व्यपगत का सिद्धांत
> - यह ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति थी, जिसके तहत दत्तक पुत्र को सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस नीति के तहत निम्न राज्यों को हड़प लिया - सतारा (1848), संबलपुर (1850), उदयपुर (1852), झांसी (1853), नागपुर (1854)।
> - बरार और अवध को कुशासन के बहाने अधिगृहित कर लिया ।

2. आर्थिक कारण:

- भारी कराधान: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी भूमि राजस्व व्यवस्थाओं के तहत किसानों पर अत्यधिक भूमि कर का बोझ डाला गया।
- भूमि सुधार: पारंपरिक जमींदारी अधिकारों को समाप्त करने से ग्रामीण समाज में अस्थिरता पैदा हुई।
- कृषि का व्यावसायीकरण: नकदी फसलों की ओर रूख करने से खाद्य आपूर्ति और आजीविका प्रभावित हुई।
- औद्योगिक पतन: ब्रिटिश नीतियों के कारण पारंपरिक हस्तशिल्प और उद्योगों का पतन हुआ।
  - ✓ व्यापार नीतियाँ: ब्रिटिश शोषणकारी व्यापार नीतियों ने भारतीय कारीगरों की अपेक्षा ब्रिटिश निर्माताओं को लाभ प्रदान किया।
- अकाल और गरीबी: अकाल की बारंबारता और आर्थिक कठिनाई ने जनता के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया।

3. प्रशासनिक कारण:

- कंपनी के प्रशासन में मुख्यतः पुलिस, छोटे अधिकारियों और निचली अदालतों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था, जिससे जनता में भारी असंतोष पैदा हुआ।
- भारतीयों को सभी श्रेष्ठ और उच्च वेतन वाली नौकरियों से बाहर रखा गया।

4. सामाजिक-धार्मिक कारण:

- लेक्स लोकी अधिनियम, 1850 के साथ भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता ने विरासत के हिंदू उत्तराधिकार कानून को बदल दिया, जिससे किसी हिंदू के ईसाई धर्म अपनाने पर भी वह अपनी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता था।
- ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों को संदेह और अविश्वास की नजर से देखा गया।

- सती प्रथा का उन्मूलन (1829, गवर्नर- विलियम बेंटिक) और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना (1856, लॉर्ड डलहौज़ी), आदि को समाज के रीति-रिवाजों में अनुचित हस्तक्षेप माना गया।
- पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ने हिंदुओं और मुसलमानों की पारंपरिक/रूढ़िवादी मान्यताओं को सीधे चुनौती दी।
- सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थीं।

5. सैन्य कारण:

- तात्कालिक कारण: चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग।
- सैन्य असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, 1856 था (लॉर्ड कैनिंग द्वारा स्थापित), जिसके तहत सिपाहियों को ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया।
- भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों के बीच वेतन, पेंशन और पदोन्नति के मामले में भेदभाव था।भारतीय सिपाहीयों को सूबेदार के पद तक सीमित कर दिया गया था ।

6. बाहरी घटनाओं का प्रभाव:

- 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं के साथ हुआ, जिनमें अंग्रेजों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा था—पहला अफ़ग़ान युद्ध (1838-42), पंजाब युद्ध (1845-49) और क्रीमियन युद्ध (1854-56)। इन घटनाओं के स्पष्ट मनोवैज्ञानिक परिणाम थे।

7. तात्कालिक कारण:

- चर्बी वाले कारतूसों का प्रकरण - नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चिकनाई लगी कागज़ की परत होती थी, जिसे राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। यह चिकनाई कुछ मामलों में गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी।
- इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही पूरी तरह से क्रोधित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही है।

Unleash the topper in you

विद्रोह का क्रम

1. सिपाही विद्रोह

- 29 मार्च, 1857: बैरकपुर में तैनात एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करते हुए विद्रोह किया। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई।
- 24 अप्रैल: मेरठ में तैनात तीसरी नेटिव कैवेलरी के 90 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था ।
- 10 मई: पूरी भारतीय रक्षक सेना ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच करने का फैसला किया। वे दिल्ली पहुंचे और वृद्ध बहादुर शाह ज़फ़र को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।
- जल्द ही बंगाल की पूरी सेना ने विद्रोह कर दिया, जो तीव्र गति से फैला । पूरा उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। मध्य भारत में भी, जहाँ शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे वहाँ सेना ने विद्रोह कर विद्रोहियों का साथ दिया। उदाहरण: इंदौर की सेना अपने शासक महाराजा होल्कार की अनिच्छा के बावजूद विद्रोह में शामिल हो गई।

2. जन विद्रोह

- विद्रोह के तुरंत बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में बगावत शुरू हो गई। जहाँ सरकारी खजाने को लूट लिया , बारूद गोदामों को तबाह कर दिया, बैरकों और न्यायालयों को जला दिया, और जेल के दरवाजे खोल दिए गए।
- इस विद्रोह में किसानों, कारीगरों, दुकानदारों, मजदूरों, जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारियों आदि का व्यापक हिस्सा था।
- किसानों और छोटे जमींदारों ने साहूकारों और उन जमींदारों पर हमला किया जिन्होंने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया था। उन्होंने साहूकारों की खाता बही और ऋण अभिलेखों को नष्ट कर दिया।
- विद्रोह की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि हिंदू-मुस्लिम एकता थी।
- सभी सिपाहियों ने सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र की सर्वोच्चता को स्वीकार किया और "दिल्ली चलो" का नारा दिया।

1857 के विद्रोह के क्षेत्रीय नेता

नेता का नाम	विद्रोह का स्थान	1857 के विद्रोह में निभाई गई भूमिका
नाना साहेब और तांत्या टोपे	कानपूर	➢ नाना साहेब, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे, ने तांत्या टोपे की मदद से अंग्रेजों को कानपूर से खदेड़ दिया और नाना साहेब को पेशवा घोषित किया, जिन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट सवीकार किया ➢ तात्या टोपे महान योद्धा थे जिन्होंने रानी लक्ष्मी बाई को ग्वालियर पर कब्जा करने में मदद की।
बेगम हज़रत महल और बिरजिस कादिर	लखनऊ	➢ अवध की बेगम ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया।
रानी लक्ष्मी बाई	झाँसी	➢ वह व्यपगत के सिद्धांत की नीति के खिलाफ थीं और अपने दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बिठाने के लिए लड़ीं। ➢ मार्च, 1858 में अंग्रेजी सेना ने झाँसी पर हमला किया; लक्ष्मी बाई अपने बेटे के साथ क़िले से भागकर वह कालपी पहुँचीं, जहाँ उन्होंने तांत्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया।
कुंवर सिंह	आरा, बिहार	➢ उनके नेतृत्व में सैन्य और नागरिक विद्रोह पूरी तरह से जुड़े हुए थे, जिस के कारण अंग्रेज सबसे अधिक डरते थे। ➢ मार्च, 1858 में कुंवर सिंह ने आज़मगढ़ पर कब्जा कर लिया ।
शाह मल	बाघपत, उत्तर प्रदेश	➢ उन्होंने 84 गांवों (जिसे चौरासी देश कहा जाता है) के प्रधानों और किसानों को एकत्रित कर रात को एक गांव से दूसरे गांव तक मार्च किया और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। ➢ उन्होंने "न्यायालय" (न्याय की ओवरी) की स्थापना की, जिसमें विवादों को निपटाकर और निर्णय दिए जाते थे।
मौलवी अहमदुल्ला	फैज़ाबाद	➢ वे अवध में विद्रोह फैलने के बाद एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे।

प्रमुख शहीद क्रांतिकारी

विद्रोह के स्थान	नेता/नेतृत्वकर्ता
बैरकपुर	मंगल पांडे
दिल्ली	बहादुर शाह II, जनरल बख्त खान, हकीम अहसानुल्लाह (बहादुर शाह II के मुख्य सलाहकार)
इलाहाबाद और बनारस	मौलवी लियाकत अली
फैज़ाबाद	मौलवी अहमदुल्ला (उन्होंने इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरूद्ध जिहाद घोषित किया)
बरेली	खान बहादुर खान
ग्वालियर/कानपुर	तात्या टोपे (इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। इनका मूल निवास येवला, महाराष्ट्र में था और बिठूर (कानपुर) में नाना साहब और मोरोपंत तांबे के संपर्क में आए।)

1857 के विद्रोह का दमन

- ब्रिटिश सेना ने लंबी और दमनात्मक लड़ाई के बाद 20 सितंबर, 1857 को दिल्ली का अधिग्रहण कर लिया। वृद्ध सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को बंदी बना लिया गया और रंगून (म्यांमार) निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई।
- 1859 के अंत तक भारत में अंग्रेजी शासन पूरी तरह से पुनः स्थापित हो गया।
- विद्रोह विफल रहा लेकिन यह व्यर्थ नहीं गया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों का पहला महान संघर्ष था तथा इसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

विद्रोह से जुड़े ब्रिटिश सेना अधिकारी

जनरल जॉन निकोलसन, विलियम हडसन, जेम्स आउट्रम	दिल्ली
जनरल नील	बनारस, इलाहाबाद और कानपुर
सर कॉलिन कैंपबेल	कानपुर और लखनऊ
हेनरी लॉरेंस	अवध के मुख्य आयुक्त -2 जुलाई, 1857 को लखनऊ में विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश निवास पर कब्ज़ा करने के दौरान मारे गए।
मेजर जनरल हैवलॉक	17 जुलाई, 1857 को विद्रोहियों (नाना साहब की सेना) को हराया। लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई।
विलियम टेलर और आई	आरा में विद्रोह को दबाया।
ह्यूग रोज़	झांसी में विद्रोह को दबाया।

विद्रोह की असफलता के कारण

1. योजना और संसाधनों की कमी

  - विद्रोहियों के पास कोई दूरदर्शी योजना नहीं थी।
  - अंग्रेजों के पास डाक, टेलीग्राम और रेलवे जैसे उन्नत संचार साधन थे, इसके विपरीत विद्रोहियों के पास ऐसे संसाधनों की कमी थी इसलिये उन्हें ऐसी सेवाएँ नहीं मिल सकीं।

2. <u>भारतीयों में एकता का अभाव</u>

- 1857 का विद्रोह अधिकतर स्थानीय मुद्दों पर आधारित था, क्योंकि विभिन्न भारतीय नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए संघर्ष किया।
- बंगाल सेना के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, जबकि पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में विद्रोह दबाने में मदद कर रहे थे।
- समाज के कुछ वर्ग विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे।
- विद्रोह का प्रसार केवल उत्तर भारत तक ही सीमित था।

3. <u>शिक्षित भारतीयों का समर्थन न मिलना</u>

- आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह विद्रोह पिछड़ेपन की ओर ले जाएगा।
- शिक्षित मध्यम वर्ग ने गलतफहमी में यह मान लिया था कि अंग्रेज देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जाएँगे।

4. <u>नेताओं के बीच एकता का अभाव</u>

- मुख्य समस्या स्वयं विद्रोहियों के बीच एकता की कमी थी।
- नेता एक-दूसरे के प्रति संदिग्ध और ईर्ष्यालु थे तथा अक्सर छोटे-मोटे झगड़ों में लिप्त रहते थे।

5. <u>अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता</u>

- विद्रोहियों की हार का एक और प्रमुख कारण अंग्रेजों के पास उन्नत हथियारों की उपलबद्धता था ।
- विद्रोहियों में अनुशासन और केंद्रीय कमान का अभाव था, जबकि अंग्रेजों को अनुशासित सैनिक, युद्ध सामग्री और धन की निरंतर आपूर्ति होती रही।

<u>विद्रोह का प्रभाव</u>

1857 के विद्रोह के विफल होने के बावजूद, इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा झटका दिया। पुनः स्थापित ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में कई मामलों में बदलाव हुए।

1. ब्रिटिश क्राउन ने 1858 के एक अधिनियम (जिसे भारत की बेहतरी के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से कंपनी पर अधिकार कर लिया।
2. सैन्य संगठन में बदलाव

- बंगाल सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल सेना में 1 यूरोपीय सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक एवं बॉम्बे और मद्रास सेना में 1 यूरोपीय सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक तय कर दिए ।
- सेना की महत्वपूर्ण शाखाएँ जैसे तोपखाना विशेष रूप से यूरोपीय सैनिकों के नियंत्रण में कर दी गई।
- सैनिकों में किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी भावना के विकास को रोकने के लिए जाति, समुदाय, धर्म और क्षेत्र (मार्शल रेस की अवधारणा) के आधार पर रेजिमेंटे बनाई गईं।

3. <u>फूट डालो और राज करो की नीति</u>

- जन साधारण के लिये भी "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाई गई, जिसके तहत सार्वजनिक नियुक्तियों और अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों को कड़ी सजा दी गई और उनके साथ भेदभाव किया गया।
- कालांतर मे इस नीति को बदलते हुए मुसलमानों का तुष्टीकरण शुरू कर दिया।
- फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया।

Unleash the topper in you

4. देशी रियासतों के प्रति नई नीति

   - विलय की नीति को अब त्याग दिया गया और शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार दिया गया।
   - जिन शासकों ने विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों का समर्थन किया, यह उन शासकों को पुरस्कार के रूप में दिया गया अधिकार था

5. नए सहयोगियो का निर्धारण

   - अंग्रेजों ने देश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जमींदारों, राजकुमारों और जागीरदारों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया।

6. श्वेत विद्रोह

   - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण से कंपनी के अधीन कार्यरत यूरोपीय बलों के एक वर्ग ने इसका विरोध किया। इस असंतोष के परिणामस्वरूप कुछ अशांति पैदा हुई जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है।

विद्रोह की प्रकृति

- डॉ. के. दत्ता 1857 के विद्रोह को विद्रोहियों के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य और उद्देश्य की एकता के अभाव से चिह्नित आंदोलन मानते हैं।
- वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक ‘द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857’ में इसे " योजनाबद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम" के रूप में व्याख्यायित किया और इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा।
- डॉ. एस.एन. सेन ने कहा कि यह सिपाही विद्रोह से अधिक था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से कम था।
- डॉ. आर.सी. मजूमदार इसे न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं।
- जवाहरलाल नेहरू ने 1857 के विद्रोह को मूलतः एक सामंतवादी विद्रोह माना, यद्यपि इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी थे (डिस्कवरी ऑफ इंडिया)।
- टी.आर. होम्स- इन्होने इस विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष माना ।
- जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया।
- यह विद्रोह सांप्रदायिक एकता का एक महान प्रतीक था।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

2
CHAPTER

शिक्षा एवं प्रेस का विकास

भारत में शिक्षा का विकास

शुरुआत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा प्रणाली के विकास से कोई सरोकार नहीं था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार और लाभ कमाना था। भारत में नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उनका उद्देश्य उच्च और मध्यम वर्ग के भारतीयों के एक छोटे समूह को शिक्षित करना था। उनका उद्देश्य ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाना था "जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन रुचि, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी हो" तथा ये व्यक्ति ब्रिटिश सरकार और व्यापक भारतीय आबादी के बीच कड़ी के रूप में कार्य कर सकते हो । इस रणनीति को "अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत" (डाउनवर्ड फ़िल्टरेशन थ्योरी) कहा जाता है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी विचारों और मूल्यों को इस छोटे से शिक्षित समूह से बड़े समाज में फैलाना था।

शैक्षिक प्रणाली के विकास में योगदान

- वारेन हेस्टिंग्स (1781): उन्होंने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की।
- जोनाथन डंकन (1791): हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की।
- लॉर्ड वेलेजली (1800): भारतीय भाषाओं और रीति-रिवाजों का प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, हालांकि इसे 1802 में बंद कर दिया गया।

1857 से पहले शिक्षा

- 1813 का चार्टर एक्ट:
  - ✓ इस एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को प्रारंभिक प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये खर्च करने का निर्देश दिया गया।
  - ✓ सरकार ने आगरा, कलकत्ता और दिल्ली में तीन संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित किये।

Note : लोक शिक्षा पर सामान्य समिति - 1823 में, भारत में शिक्षा के मामलों पर कंपनी को मार्गदर्शन देने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इसमें शिक्षा के माध्यम और विषय-वस्तु पर निर्णय लेने के लिए आंग्लवादी और प्राच्यवादी दोनों का प्रतिनिधित्व था।

आंग्लवादी और प्राच्यवादी विवाद

- भारत में शिक्षा प्रदान करने की विषय-वस्तु और माध्यम से संबंधित विवाद ने आंग्लवादी-प्राच्यवादी विवाद को जन्म दिया।
- आंग्लवादी: विद्वानों का यह समूह मानता था कि पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। इस समूह के एक प्रमुख विद्वान थॉमस बैबिंगटन मैकाले थे।
- प्राच्यवादी: विद्वानों का यह समूह स्थानीय भाषाओं के माध्यम से पारंपरिक भारतीय शिक्षा के अध्ययन की वकालत कर रहा था। इस समूह के एक प्रमुख विद्वान एच.टी. प्रिंसेप थे।
- अंततः थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने इस विवाद को सुलझाया, इन्होने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को अदालतों की आधिकारिक भाषा बनाया और सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी कर दिया।के रूप में चुना तथा सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी को ही बनाया।

लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र, 1835

- लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र ने आंग्लवादी दल का समर्थन किया - जिसमें पश्चिमी विज्ञान और साहित्य की शिक्षा केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देने की बात कही गई।
- उन्होंने 'अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत' को बढ़ावा दिया, जिसके अनुसार शिक्षित भारतीयों की एक छोटी संख्या पश्चिमी शिक्षा के अपने ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाएगी।

चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच (1854)

- चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच को 'भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है।
- सिफारिशों
  - ✓ इसने आम जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार से लेने को कहा, इस प्रकार इसमें अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को खारिज कर दिया।
  - ✓ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी, तत्पश्चात एंग्लो-वर्नाक्युलर हाई स्कूल तथा उच्च शिक्षा स्तर (कॉलेज) में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।
  - ✓ इसमें महिला एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया।
  - ✓ सरकार निजी स्कूलों और कॉलेजों को अनुदान के रूप में वित्त पोषण उपलब्ध कराएगी।
  - ✓ सरकारी संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए।
- वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर
  - ✓ 1857: कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये।
  - ✓ सभी प्रमुख प्रान्तों में शिक्षा विभाग स्थापित किये गये।
  - ✓ पूसा (बिहार) में कृषि संस्थान और रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई।

1857 के बाद शिक्षा

हंटर शिक्षा आयोग (1882-83)

- 1882: डब्ल्यू.डब्ल्यू.हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया।
- उद्देश्य: 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद से भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना।
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित सिफारिशें -
  - ✓ प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग हो ।
  - ✓ प्राथमिक शिक्षा को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए जिला एवं नगरपालिका बोर्डों को सशक्त बनाना चाहिए।
  - ✓ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा पर जोर दिया गया
  - ✓ सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा में दो विभाग होने चाहिए – साहित्यिक विभाग और व्यावहारिक विभाग।
- पंजाब विश्वविद्यालय (1882) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय (1887) की स्थापना आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 (रैले आयोग)

- 1902: भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए टॉमस रैले की अध्यक्षता में रैले आयोग गठित किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम के अनुसार -
  - ✓ विश्वविद्यालयों को अध्ययन और अनुसंधान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

toppersnotes unleash the topper in you

- ✓ विश्वविद्यालय के उप-सदस्यों (fellows) की संख्या और उनके कार्यकाल की अवधि कम कर दी गई तथा अधिकांश उप-सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किए जाने का प्रावधान किया गया।
- ✓ सरकार को विश्वविद्यालयों के सीनेट विनियमों/प्रस्तावों को वीटो करने का अधिकार दिया गया तथा वह इन विनियमों में संशोधन कर सकती थी।
- ✓ निजी कॉलेजों की संबद्धता के लिए शर्तें सख्त की जानी चाहिए
- ✓ उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के उत्थान हेतु प्रति वर्ष पांच लाख रुपये की राशि, पांच वर्षों के लिए, मंजूर की गई।

सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग) (1917-19)

- ➢ अध्यक्ष - माइकल सैडलर
- ➢ उद्देश्य: कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना और उन पर रिपोर्ट देना, लेकिन इसमें स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा की गई।
- ➢ इसने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया की स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, क्योंकि यह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक पूर्व शर्त थी। इसने विश्वविद्यालय के नियमों को तैयार करने में लचीलेपन की भी वकालत की।

हार्टोग समिति (1929)

- ➢ स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षा की बिगड़ती गुणवत्ता की जाँच करना।
- ➢ सिफारिशें
  - ✓ निरक्षरता दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा की महत्वता पर बल देने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए तथा सरकार को मात्रा के बजाय गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देना चाहिए।
  - ✓ केवल योग्य छात्रों को ही उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर प्रवेश दिया जाना चाहिए, जबकि औसत छात्रों को आठवीं कक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

Unleash the topper in you

सार्जेंट शिक्षा योजना (1944)

- ➢ सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे , जिन्होंने एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की।
- ➢ सिफारिशें
  - ✓ 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान।
  - ✓ 6-11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।
  - ✓ 11-17 वर्ष आयु वर्ग के चुनिंदा बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और इसके बाद त्रिवर्षीय स्नातक शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- ➢ उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को समाप्त करने की सिफारिश की गई।
- ➢ उच्च शिक्षा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा
  - ✓ विधा विषयक शिक्षा
  - ✓ तकनीकी और व्यावसायिक
- ➢ अगले 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए
- ➢ शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया ।

मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना (1937)

- अक्टूबर 1937 (वर्धा): कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और इसमें पारित प्रस्ताव के अंतर्गत, जाकिर हुसैन समिति ने "गतिविधि के माध्यम से सीखने" के सिद्धांत पर आधारित बुनियादी शिक्षा के लिए एक योजना तैयार की। यह योजना गांधीजी के हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला पर आधारित थी।
- इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान थे।
  - ✓ पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तशिल्प और दस्तकारी कौशल को शामिल करना।
  - ✓ स्कूली शिक्षा के प्रथम सात वर्षों तक सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
  - ✓ कक्षा 2 से 7 तक हिन्दी में तथा कक्षा 8 के बाद केवल अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए।
  - ✓ सेवा के माध्यम से स्कूलों के आसपास के समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करना।

शिक्षा में स्वदेशी प्रयास

- राजा राम मोहन राय: आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने 1813 के चार्टर अधिनियम को पारित करने में मदद की।
- राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, 1906: स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इसका प्रयोग एक केन्द्र के रूप में किया गया।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई ।
- बनारस में काशी विद्यापीठ, अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई ।
- गांधीजी की नई तालीम (या बुनियादी शिक्षा) योजना छात्रों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने पर केंद्रित थी।

मुद्रण (प्रेस) का विकास

- भारत में प्रेस का इतिहास पुर्तगालियों के आगमन से शुरू हुआ, जिन्होंने गोवा में पहला मुद्रणालय स्थापित किया था।
- जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, द बंगाल गजट/ कलकत्ता जनरल एडवरटाइज़र (अंग्रेजी साप्ताहिक) प्रकाशित किया गया (सरकार की आलोचना करने के कारण इसे 1782 में जब्त कर लिया गया था)।
- धीरे-धीरे और भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जैसे द बंगाल जर्नल, द कलकत्ता क्रॉनिकल, द मद्रास कूरियर, द बॉम्बे हेराल्ड आदि।

प्रेस सेंसरशिप अधिनियम/ पत्रेक्षण अधिनियम 1799

- लॉर्ड वेलेजली द्वारा अधिनियमित।
- इस अधिनियम ने युद्धकालीन प्रेस प्रतिबंध (भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका) लगा दिए, जिसमें पूर्व-सेंसरशिप भी शामिल थी, क्योंकि इसके तहत प्रकाशक को मुद्रण से पहले सभी सामग्री प्रस्तुत करनी होती थी और मुद्रक, संपादक और स्वामी का नाम छापना होता था।

अनुज्ञप्ति विनियम, 1823 (Licensing Regulations of 1823)

- सर थॉमस मुनरो की सिफारिशों पर जॉन एडम्स द्वारा अधिनियमित
- बिना लाइसेंस प्राप्त किये कोई भी प्रेस स्थापित नहीं की जा सकती।
- मजिस्ट्रेटों को नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रेसों को सील करने का अधिकार दिया गया तथा उल्लंघन की स्थिति में गवर्नर-जनरल लाइसेंस रद्द कर सकता था।

- ये प्रतिबंध स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों के विरुद्ध थे।
- राजा राममोहन राय को 'मिरात-उल-अखबार' का प्रकाशन बंद करना पड़ा।

- अंग्रेजी और स्थानीय समाचार-पत्रों के सम्पादकों की याचिकाओं की प्रतिक्रिया में बेंटिंक ने प्रेस अधिनियम 1835 या मेटकाफ अधिनियम के द्वारा प्रेस कानूनों में सुधार किया। इसी क्रम में उसने प्रेस स्वतंत्रता को बाधित करने वाले वर्ष 1823 के लाइसेंसिंग विनियमों को प्रतिस्थापित किया।
  - ✓ हालांकि इससे प्रेस की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, किन्तु पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई।
- बेंटिंक के कार्यकाल के बाद मेटकाफ ने प्रेस स्वतंत्रता की दिशा में बहुत से कदम उठाए। इसीलिए मेटकाफ को "भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता" कहा गया।

लाइसेंसिंग अधिनियम, 1857

- लाइसेंसिंग प्रतिबंध लगाए गए।
- सरकार ने किसी भी मुद्रित सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को रोकने का अधिकार सुरक्षित रखा।

1867 का पंजीकरण अधिनियम

- 1835 के मेटकाफ अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया।
- अख़बार को मुद्रक, प्रकाशक और प्रकाशन स्थल का नाम बताना ज़रूरी था। साथ ही, उन्हें प्रकाशन के एक महीने के भीतर स्थानीय सरकार को एक निःशुल्क प्रति भी जमा करानी आवश्यक थी।

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878

- स्थानीय साहित्य में राजद्रोही लेखन को रोकने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा इसे एक प्रतिक्रियात्मक नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह जिला मजिस्ट्रेटों को किसी भी स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को यह कहने का अधिकार देता है कि वे ऐसा कुछ भी प्रकाशित न करें जिससे सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा हो।
- मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होता था और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी।
- इस अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए 'अमृत बाजार पत्रिका' रातोंरात अंग्रेजी अखबार में बदल गई।
- 1882: अंततः लॉर्ड रिपन ने इस विवादास्पद अधिनियम को निरस्त कर दिया।
- 1883: सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ऐसे पहले भारतीय पत्रकार थे, जिन्हें बंगाली अखबार में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आलोचना करने वाले संपादकीय के कारण जेल जाना पड़ा।

समाचार पत्र (अपराधों को उकसाना) अधिनियम, 1908

- इस अधिनियम के तहत, सरकार किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर सकती थी यदि उसने कोई ऐसी चीज छापी हो जो सरकार को आपत्तिजनक और अपमानजनक लगे तथा जिससे हत्या या हिंसा के लिए उकसाया जा सके।

भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931

- इस अधिनियम का उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अंकुश लगाना था क्योंकि इसने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करने और उन पर लाठीचार्ज करने का अधिकार दिया था।

राष्ट्रवाद और साहित्यिक विकास

समाचार-पत्र / जर्नल	संस्थापक/संपादक
बंगाल गजट, 1780	जेम्स ऑगस्टस हिकी
भारत गजट, 1787	हेनरी लुईस विवियन डेरोज़ियो
कलकत्ता जर्नल, 1818	जे एस बकिंघम
बंगाल गजट (पहला बंगाली अखबार)	हरिश्चंद्र राय
संवाद कौमुदी (बंगाली - साप्ताहिक)	राजा राममोहन राय
मिरात-उल-अखबार (पहली फ़ारसी पत्रिका)	राजा राममोहन राय
बंग-दत्त, 1822	राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, और अन्य
ईस्ट इंडियन (दैनिक), 1831	हेनरी विवियन डेरोज़ियो
रास्त गोफ्तार (पाक्षिक - गुजराती), 1851	दादाभाई नौरोजी
हिन्दू पैट्रियट, 1853	गिरीश चंद्र घोष (बाद में, हरिश्चंद्र मुखर्जी मालिक-सह-संपादक बने)
सोमप्रकाश	द्वारकानाथ विद्याभूषण.
इंडियन मिरर	देवेन्द्रनाथ टैगोर
बंगाली	गिरीश चंद्र घोष (1879 में एस.एन. बनर्जी द्वारा कार्यभार संभाला गया)
अमृत बाज़ार पत्रिका (शुरुआत में बंगाली में प्रकाशित हुई एक दैनिक पत्रिका जो बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई,) 1868	शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष
बंगदर्शन (बंगाली में), 1873	बंकिमचंद्र चटर्जी
द हिन्दू (अंग्रेजी साप्ताहिक), 1878	जीएस अय्यर, वीरराघवचारी
केसरी (मराठी- दैनिक) और मराठा (अंग्रेजी-साप्ताहिक), 1881	बाल गंगाधर तिलक
स्वदेशमित्रम (तमिल पेपर), 1882	जीएस अय्यर
युगांतर	बरिन्द्र कुमार घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त
संध्या	ब्रह्मबांधव उपाध्याय
कल	बाल गंगाधर तिलक और प्रणजपे
भारतीय समाजशास्त्री	श्यामजी कृष्णवर्मा
बंदे मातरम	मैडम भीकाजी कामा
तलवार	वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय
आज़ाद हिंदुस्तान	तारकनाथ दास
कॉमरेड (अंग्रेजी) और हमदर्द (उर्दू)	मोहम्मद अली जिन्ना
ग़दर, 1913	ग़दर पार्टी
बॉम्बे क्रॉनिकल	फिरोजशाह मेहता, संपादक—बी.जी. हॉर्निमैन (अंग्रेज) द्वारा प्रारंभ किया गया
नया भारत और राष्ट्रमंडल	एनी बेसेंट
द इंडिपेंडेंट	मोतीलाल नेहरू

हिंदुस्तान टाइम्स	के.एम. पणिक्कर
लीडर (अंग्रेजी में)	मदन मोहन मालवीय
बहिष्कृत भारत (मराठी पाक्षिक), 1927	बी.आर. अंबेडकर
बंदी जीवन, 1922	सचिन्द्रनाथ सान्याल
नेशनल हेराल्ड (दैनिक), 1938	जवाहरलाल नेहरू
पंजाबी, वंदे मातरम, लोग, कौमी आवाज	लाला लाजपत राय

महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके लेखक

लेखक	पुस्तक
1. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय	➢ राजमोहन की पत्नी ➢ दुर्गेशनंदिनी ➢ कपालकुंडला ➢ आनंदमठ (इसमें "वंदे मातरम्" को प्रस्तुत किया, जिसने प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया।)
2. जेम्स मिल	➢ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया (भारतीय धर्म, संस्कृति और समाज की आलोचना करते हुए, इसे पिछड़ा और हीन बताया।)
3. दादाभाई नौरोजी	➢ पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (भारत में ब्रिटिश शासन के तहत धन के आर्थिक दोहन को उजागर किया और भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद का सूत्रपात किया।)
4. आर.सी. दत्त	➢ इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया
5. बाल गंगाधर तिलक	➢ द आर्कटिक होम इन द वेदास

Toppersnotes
Unleash the topper in you